अध्याय 07 : नागरिकता (Citizenship)

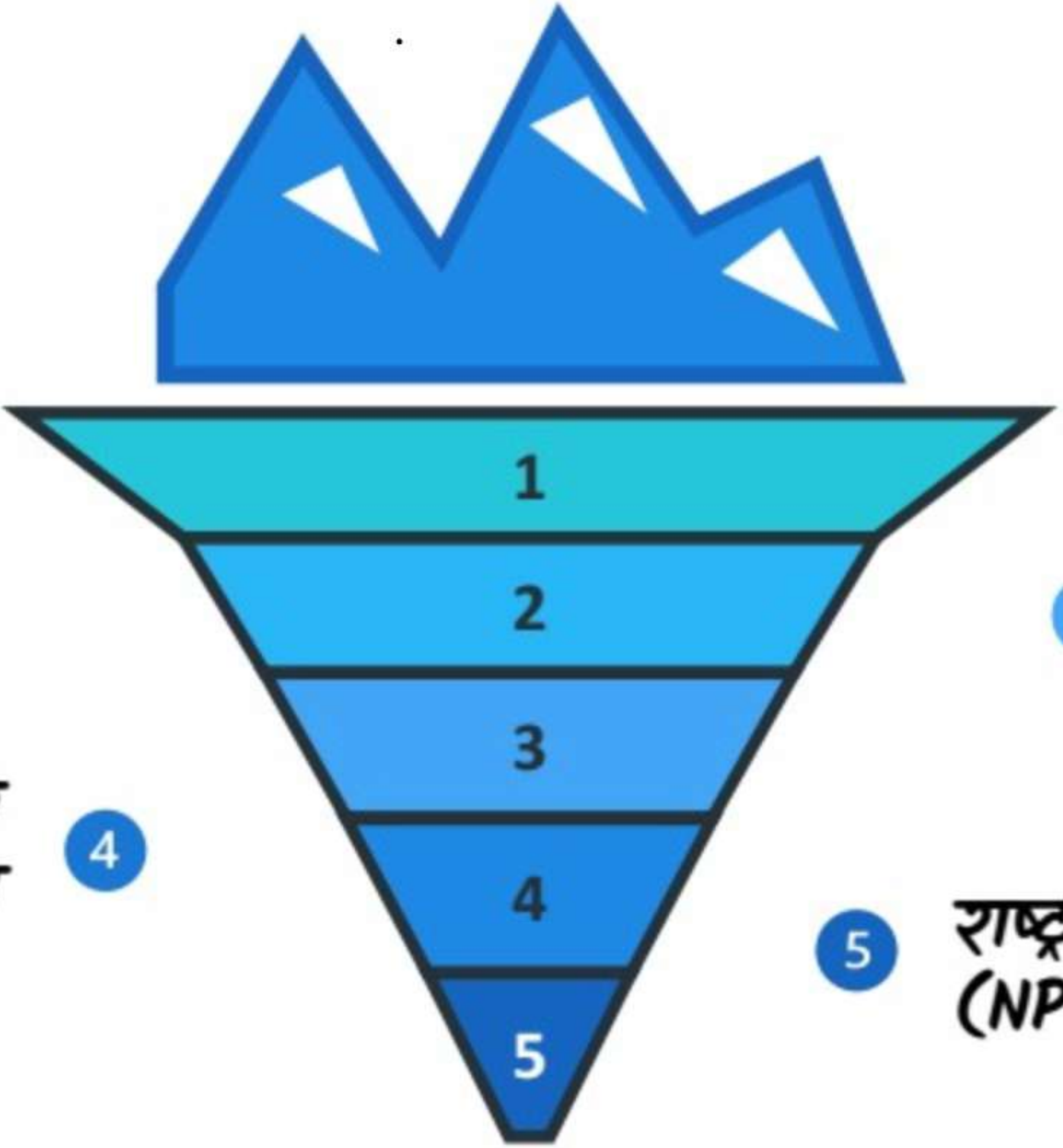

1. सामान्य परिचय
2. नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद
3. भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955
4. विदेशियों के लिए नागरिकता
5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR = 2004-05)

नागरिकता (Citi)

- भाग 2 (PAR 2)
- 05 से 11
- एकल नागरिकता (Single Citi) ← ब्रिटेन (UK)
- नागरिकता अधिनियम 1955 (Citi Act 1955)

05

→ 26 जनवरी 1950
- जन्म (Birth) = India
- पिछले 5 वर्षों से भारत (Domi. = India)
- माता या पिता (जन्म : भारत)

06

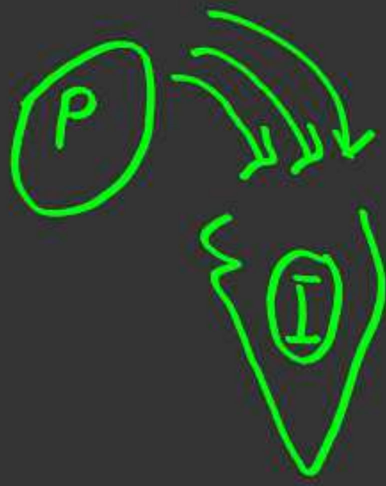

07

06 ⇒ पाकिस्तान से भारत
- खुद | Self
- माता-पिता
- दादा-दादी
- नाना-नानी

→ अविभाजित भारत

07
- भारत से पाकिस्तान
- फिर पाकिस्तान से भारत

> परमिट Permit

08 → 26 JAN 1950

कनाडा

UK

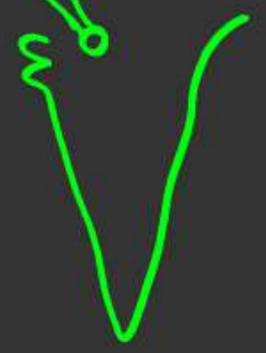

प्रमाण
- स्वयं / Self
- माता - पिता
- दादा - दादी
- नाना - नानी

UK = India Emb / भारतीय दूतावास

⇓

जानकारी (Information)

09

- एकल नागरिकता (Single Citi)
- भारत का नागरिक (India Citizen)
  - ↓ यदि (if) ⟹ किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारतीय नागरिकता समाप्त।

11

→ नागरिकता (Citi) →

संसद को कानून बनाने की शक्ति
Regarding citizenship = Law = Only Parliament

↓

भारतीय नागरिकता Act 1955
Citi Act 1955

नागरिकता अधिनियम 1955
Citi Act 1955

- नागरिकता (Cit) ⇒ संघ सूची | Union list
- 30 दिसंबर 1955
- हालिया संशोधन | Recent Am ⇒ 2019
  - CAA
- अर्जित (How to be cit India)
  - 5
- समाप्त | End
  - 3

Chapter 07 : Citizenship

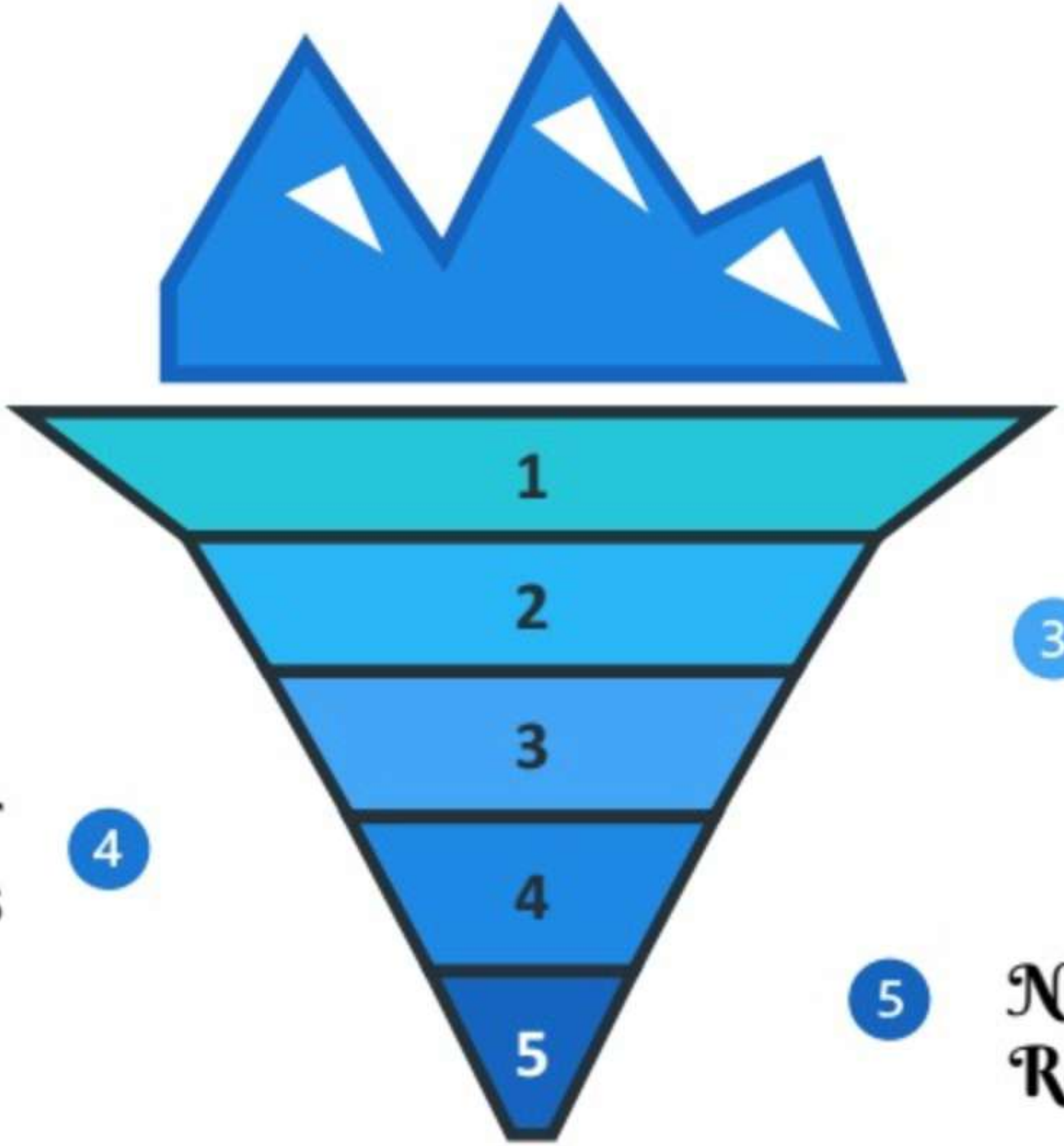

1 General Introduction

2 Key Articles Related to Citizenship

3 Indian Citizenship Act, 1955

4 Citizenship for Foreigners

5 National Population Register (NPR = 2004-05)

1) सामान्य परिचय (Introduction)

भाग 02 → अनुच्छेद 5 से 11 → ब्रिटेन से एकल नागरिकता (Single Citizenship)

"नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच का वह कानूनी और राजनीतिक संबंध है, जिसके तहत व्यक्ति को उस देश की पूर्ण सदस्यता, संरक्षण एवं अधिकार प्राप्त होती है।"

निवासियों की चार श्रेणियां

- नागरिक (Citizens)
- विदेशी (Foreigners) → मित्र राष्ट्र के और शत्रु देश
- शरणार्थी (Refugee) → स्थायी या अस्थायी
- अवैध प्रवासी (Illegal Immigrants) → बिना वैध दस्तावेजों के देश में

भाग 02 → अनुच्छेद 5 से 11

नागरिकता अधिनियम, 1955

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

नागरिकता (संशोधन) → 1986 + 1992 + 2003 (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) + 2005 + 2015 + 2019

National Register of Citizens (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर)

1) General Introduction

Part 02 → Articles 5 to 11 → Single Citizenship (borrowed from Britain)

"Citizenship is the legal and political relationship between a person and a state, under which the person receives full membership, protection, and rights of that country."

Four Categories of Residents

- **Citizens**
- **Foreigners** → from friendly nations and enemy countries
- **Refugee** → permanent or temporary
- **Illegal Immigrants** → in the country without valid documents

Part 02 → Articles 5 to 11

Citizenship Act, 1955

Citizenship (Amendment) Act, 2019

Citizenship (Amendments) → 1986 + 1992 + 2003 (Overseas Citizen of India) + 2005 + 2015 + 2019

National Register of Citizens

2) नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद-5
संविधान प्रारंभ पर नागरिकता

अनुच्छेद-6
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद-7
पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद-8
भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद-9
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।

अनुच्छेद-10
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

अनुच्छेद-11
संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

2) Key Articles Related to Citizenship

- **Article 5** — Citizenship at the commencement of the Constitution
- **Article 6** — Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan
- **Article 7** — Rights of citizenship of certain persons who have migrated to Pakistan
- **Article 8** — Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India
- **Article 9** — Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens
- **Article 10** — Continuance of the rights of citizenship
- **Article 11** — Parliament to regulate the right of citizenship by law

❑ अनुच्छेद 05 → संविधान प्रारंभ पर नागरिकता

- 26 जनवरी 1950 को वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में **अधिवास (Domicile)** है और जो निम्नलिखित तीन में से कम से कम कोई एक शर्त पूरी करता हो:
  1) उसका **जन्म भारत** के राज्यक्षेत्र में हुआ हो।
  2) उसके **माता या पिता** में से किसी एक का जन्म भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ हो।
  3) वह संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम **5 वर्षों तक भारत के राज्यक्षेत्र में सामान्य रूप** से निवासी रहा हो।

❑ अनुच्छेद 06 → पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता

- यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों की बात करता है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान वाले क्षेत्रों से भारत आ गए थे।
- निम्न शर्तों को पूर्ण करने की अवस्था में ही भारत का नागरिक माना जाएगा:
  1) व्यक्ति का **स्वयं, या उसके माता-पिता, या दादा-दादी (पितामह-पितामही) या नाना-नानी (मातामह-मातामही)** में से किसी एक का जन्म 'अविभाजित भारत' में हुआ हो।
  2) प्रवासियों को **19 जुलाई 1948 (परमिट प्रणाली लागू)** के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया:
     - 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले → स्वतः ही भारत का नागरिक
     - 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद → नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक था। पंजीकरण के लिए यह अनिवार्य शर्त थी कि आवेदन करने से ठीक पहले वे कम से कम 6 महीने तक भारत में रह चुके हों।

❑ Article 05 → Citizenship at the commencement of the Constitution

- On 26 January 1950, every person who has a domicile in the territory of India and fulfills at least one of the following three conditions shall be considered a citizen of India :
  1) He/she was born in the territory of India.
  2) Either of his/her parents was born in the territory of India.
  3) He/she has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately before the commencement of the Constitution.

❑ Article 06 → Citizenship of persons who migrated from Pakistan to India

- This article deals with the rights of those people who came to India from the areas that became Pakistan after Partition.
- A person shall be considered a citizen of India only if the following conditions are met :
  1) The person himself/herself, or either of his/her parents, or any of his/her grandparents (paternal or maternal) was born in 'undivided India'.
  2) Migrants were divided into two categories based on 19 July 1948 (when the Permit System came into force) :
     - Those who came before 19 July 1948 → automatically became citizens of India
     - Those who came on or after 19 July 1948 → had to register for citizenship. The mandatory condition for registration was that they must have resided in India for at least 6 months immediately before applying.

- **अनुच्छेद 07 → पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।**
    - अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, तो उसे सामान्य रूप से भारत का नागरिक नही माना जाएगा।
    - In short = पाकिस्तान गया + बाद में 'स्थायी पुनर्वास परमिट' लेकर भारत वापस आया → नागरिकता
- **अनुच्छेद 08 → भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।**
    - जो व्यक्ति विदेश में रह रहा है, लेकिन उसका संबंध भारत से है, उसे कुछ शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिक माना जा सकता था।:
        - ✓ उस व्यक्ति का **स्वयं, या उसके माता-पिता, या दादा-दादी (पितामह-पितामही) या नाना-नानी (मातामह-मातामही)** में से किसी एक का **जन्म** भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत परिभाषित 'अविभाजित भारत' में हुआ हो।
        - ✓ वह व्यक्ति **भारत और पाकिस्तान के अलावा** किसी अन्य देश में सामान्य रूप से रह रहा हो।
        - ✓ उसने उस देश में स्थित **भारतीय दूतावास** में भारत के नागरिक के रूप में अपना **पंजीकरण क**रवा लिया हो।
    - यह पंजीकरण संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) से पहले या उसके बाद, कभी भी किया जा सकता था।
    - अनुच्छेद-8 = विदेश में रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति + भारतीय दूतावास में पंजीकरण = नागरिकता।
- **अनुच्छेद 09 → विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।**
    - यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा।
    - भारत में **'एकल नागरिकता' (Single Citizenship)** के सिद्धांत को स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है

- **Article 07 → Rights of citizenship of certain persons who migrated to Pakistan**
  - If any person migrated from India to Pakistan after 1 March 1947, he/she shall not ordinarily be considered a citizen of India.
  - In short = Went to Pakistan + later returned to India with a 'Permanent Resettlement Permit' → gets citizenship
- **Article 08 → Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India**
  - A person living abroad but having a connection to India could be considered an Indian citizen based on certain conditions :
    - ✓ The person himself/herself, or either of his/her parents, or any grandparent was born in 'undivided India' as defined under the Government of India Act, 1935.
    - ✓ The person is ordinarily residing in a country other than India and Pakistan.
    - ✓ He/she has registered as a citizen of India at the Indian diplomatic mission in that country.
  - This registration could be done at any time, before or after the commencement of the Constitution (26 January 1950).
  - Article 8 = Person of Indian origin living abroad + Registration at Indian Embassy = Citizenship
- **Article 09 → Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens**
  - If any person has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, he/she shall no longer be considered a citizen of India.
  - This is the most important provision establishing the principle of 'Single Citizenship' in India.

❑ अनुच्छेद 10 → नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।

- अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक माना गया है, तो वह आगे भी भारत का नागरिक रहेगा।
  - ✓ लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से जुड़े नियम बना सकती है।
- अनुच्छेद-10 = नागरिकता जारी रहेगी, लेकिन संसद के कानूनों के अधीन।
- अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता की **"सुरक्षा की गारंटी"** है।

❑ अनुच्छेद 11 → संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन।

- यह अनुच्छेद **संसद (Parliament)** को यह पूर्ण और सर्वोच्च शक्ति देता है कि वह नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर भविष्य के **लिए कानून बना** सकती है।
- संविधान ने **राज्य विधानसभाओं (State Legislatures) को नागरिकता पर कानून बनाने का कोई अधिकार नही** दिया है
- संसद नागरिकता से जुड़े इन विषयों पर कानून बना सकती है—
  - ✓ नागरिकता प्राप्त करना
  - ✓ नागरिकता समाप्त होना
  - ✓ नागरिकता छोड़ना
  - ✓ नागरिकता छिनना
  - ✓ नागरिकता से जुड़े अन्य नियम
- इसी शक्ति के आधार पर संसद ने **नागरिकता अधिनियम, 1955** बनाया।

❑ Article 10 → Continuance of the rights of citizenship

- If any person has been considered a citizen of India under Articles 5, 6, 7, or 8, he/she shall continue to be a citizen of India.
    - ✓ However, Parliament has the power to make laws relating to citizenship
- Article 10 = Citizenship shall continue, but subject to the laws made by Parliament.
- Article 10 is the **"guarantee of security"** for your citizenship.

❑ Article 11 → Parliament to regulate the right of citizenship by law

- This article gives Parliament complete and supreme power to make laws for the future on any matter related to citizenship.
- The Constitution has not given any power to State Legislatures to make laws on citizenship.
- Parliament can make laws on the following matters related to citizenship -
    - ✓ Acquisition of citizenship
    - ✓ Termination of citizenship
    - ✓ Renunciation of citizenship
    - ✓ Deprivation of citizenship
    - ✓ Other rules related to citizenship
- Based on this power, Parliament enacted the Citizenship Act, 1955.

3) भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955

1) **30 दिसंबर, 1955**
   - भारतीय नागरिकता प्राप्त करने (Acquisition) और उसकी समाप्ति (Termination) के नियमों को निर्धारित करता है।
   - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

2) नागरिकता **'संघ सूची' (Union List)** का विषय है।

3) **नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके (Acquisition) →**
   - जन्म से (By Birth
   - वंश द्वारा (By Descent)
   - पंजीकरण द्वारा (By Registration)
   - प्राकृतिककरण द्वारा (By Naturalization)
   - क्षेत्र के समावेशन द्वारा (Incorporation of Territory)

4) **नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके (Termination)**
   - स्वैच्छिक त्याग (Renunciation)
   - बर्खास्तगी (Termination)
   - वंचना (Deprivation)

5) **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 - CAA**
   - पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
   - इन समुदायों के लिए प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।

3) Indian Citizenship Act, 1955

1) **30 December, 1955**
   - It lays down the rules for the Acquisition and Termination of Indian citizenship
   - Citizenship (Amendment) Act, 2019
2) Citizenship is a subject under the 'Union List'.
3) **5 Ways of Acquiring Citizenship →**
   - By Birth
   - By Descent
   - By Registration
   - By Naturalization
   - Incorporation of Territory
4) **3 Ways of Termination of Citizenship**
   - Renunciation
   - Termination
   - Deprivation
5) **Citizenship (Amendment) Act, 2019 – CAA**
   - 6 minority communities (Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian) who came to India from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan before 31 December 2014 shall not be treated as illegal immigrants.
   - For these communities, the mandatory period of residence for acquiring citizenship by naturalization has been reduced from 11 years to 5 years.

भारतीय नागरिकता
(CITIZENSHIP)

नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके
Acquisition of Citizenship

1. जन्म से (By Birth)
2. वंश द्वारा (By Descent)
3. पंजीकरण द्वारा (By Registration)
4. प्राकृतिककरण द्वारा (By Naturalization)
5. क्षेत्र के समावेशन द्वारा (Incorporation of Territory)

नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके
Termination of Citizenship

1. स्वैच्छिक त्याग (Renunciation)
2. बर्खास्तगी (Termination)
3. वंचना (Deprivation)

★ ★ जानें · समझें · अधिकार करें ★ ★

INDIAN CITIZENSHIP
(CITIZENSHIP)
CONSTITUTION OF INDIA
5 METHODS OF
ACQUIRING CITIZENSHIP
1. BY BIRTH
2. BY DESCENT
3. BY REGISTRATION
4. BY NATURALIZATION
5. BY INCORPORATION OF TERRITORY
3 METHODS OF
TERMINATION OF CITIZENSHIP
1. VOLUNTARY RENUNCIATION
2. TERMINATION
CITIZENSHIP
3. DEPRIVATION
CITIZENSHIP
REVOKED
KNOW • UNDERSTAND • ACT

1. जन्म से (By Birth)

भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए:

① 1 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच: जन्म लेने वाला व्यक्ति जन्म से नागरिक माना जाएगा।

② 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद: जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।

③ 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद: माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी (Illegal Immigrant) न हो।

2. वंश के आधार पर (By Descent)

भारत के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए:

① 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच: जन्म के समय पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।

② 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद: जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।

(नोट: जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है।)

3. पंजीकरण द्वारा (By Registration)

(अवैध प्रवासियों को छोड़कर)

- भारतीय मूल का व्यक्ति: जो आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो।
- भारतीय से विवाह: वह विदेशी व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और आवेदन से पूर्व 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो।
- नाबालिग बच्चे: जिनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं।

4. देशीयकरण द्वारा (By Naturalisation)

- कोई भी विदेशी (जो अवैध प्रवासी न हो) यदि वह आवेदन से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहा ho.
- उन 12 महीनों से पूर्व के 14 वर्षों में से कम से कम 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों। (CAA 2019 के तहत कुछ श्रेणियों के लिए इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है)।

5. क्षेत्र समावेशन द्वारा (By Incorporation of Territory)

यदि कोई नया क्षेत्र (Territory) भारत का हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर यह निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक माने जाएंगे।

5 Ways of Acquisition of Citizenship

1. By Birth

For a person born in India:

① 1 January 1950 to 1 July 1987: A person born during this period shall be considered a citizen by birth.

② On or after 1 July 1987: At the time of birth, either the mother or the father must be an Indian citizen.

③ On or after 3 December 2004: Either the mother or the father must be an Indian citizen, and the other must not be an Illegal Immigrant.

2. By Descent

For a person born outside India:

① 26 January 1950 to 10 December 1992: At the time of birth, the father must be an Indian citizen.

② On or after 10 December 1992: At the time of birth, either the mother or the father must be an Indian citizen.

Note: The birth must be registered at an Indian Consulate within 1 year of birth.

3. By Registration

(Excluding Illegal Migrants)

- Person of Indian Origin: Must have been residing in India for at least 7 years immediately before applying.
- By Marriage: A foreign person married to an Indian citizen and residing in India for 7 years before the application.
- Minor Children: Whose parents are Indian citizens.

4. By Naturalisation

- Any foreigner (who is not an illegal migrant) if he or she has resided in India continuously for 12 months immediately before applying.
- In the 14 years preceding those 12 months, he or she must have spent at least 11 years in India. (Under CAA 2019, this has been reduced to 5 years for certain categories.)

5. By Incorporation of Territory

If a new Territory becomes part of India, the Central Government specifies through a notification in the Official Gazette which persons of that territory shall be deemed to be Indian citizens.

नागरिकता अधिनियम के महत्वपूर्ण संशोधन (Important Amendments)

- ☆ **1986 का संशोधन:** → जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए माता या पिता में से किसी एक के भारतीय होने की शर्त जोड़ी गई।
- ☆ **2003 का संशोधन:** → 'अवैध प्रवासी' (Illegal Migrant) की स्पष्ट परिभाषा दी गई और राष्ट्रमंडल नागरिकता (Commonwealth Citizenship) के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
- ☆ **2015 का संशोधन:** → PIO (Person of Indian Origin) और OCI (Overseas Citizen of India) कार्ड योजनाओं का विलय कर 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर' (OCI Cardholder) योजना बनाई गई।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA 2019):

- ☆ **प्रावधान:** → पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

  March 11, 2024,

- ☆ **छूट:** → इन समुदायों के लिए प्राकृतिकरण (Naturalisation) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की अनिवार्य अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।

Important Amendments to the Citizenship Act (Important Amendments)

- **1986 Amendment:** → For citizenship by birth, the condition was added that either the mother or the father must be an Indian citizen.
- **2003 Amendment:** → A clear definition of 'Illegal Migrant' was introduced, and the provision of Commonwealth Citizenship was abolished.
- **2015 Amendment:** → The PIO (Person of Indian Origin) and OCI (Overseas Citizen of India) card schemes were merged to create the 'OCI Cardholder' scheme.

Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA 2019):

- **Provision:** → People belonging to 6 minority communities (Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian) who came to India from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan before 31 December 2014 will not be treated as illegal migrants.

March 11, 2024,

- **Exemption:** → For these communities, the mandatory period of residence required to obtain citizenship by naturalisation was reduced from 11 years to 5 years.

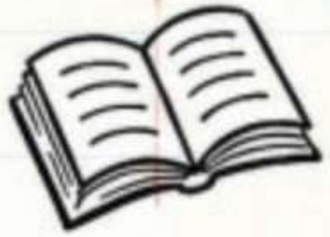

4) विदेशियों के लिए नागरिकता

1) सन् 2000 में **डॉ. एल. एम. सिंघवी** की अध्यक्षता में समिति का गठन

2) 9 जनवरी → **प्रवासी भारतीय दिवस (2003)**

श्रेणी	*विवरण*
अनिवासी भारतीय (NRI)	*वे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहते हैं।* *वीज़ा पर विदेश में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहना*
भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)	*वे विदेशी नागरिक जिनके पूर्वज भारतीय थे।*
भारत के सीमापारीय नागरिक (OCI)	*वे जिन्हें भारत द्वारा विशेष दर्जा प्रदान किया गया है।*

विवरण	**1. NRI (अनिवासी भारतीय - Non-Resident Indian)**	**2. PIO (भारतीय मूल के व्यक्ति - Person of Indian Origin)**	**3. OCI (समुद्रपारीय नागरिकता - Overseas Citizenship of India)**
नागरिकता / परिभाषा	पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक	वर्तमान में भारतीय नागरिक नही	यह पूर्ण नागरिकता नही, केवल एक दर्जा (Status) है
निवास / जारी वर्ष	वीज़ा पर विदेश में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहना	PIO कार्ड मुख्य रूप से 2002 में जारी	**शुरुआत:** 2003 **समिति:** एल. एम. सिंघवी समिति (गठन 2000 | रिपोर्ट 2002)
संबंधित अधिनियम / विस्तार	• पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 • विदेशी अधिनियम (Foreigner Act), 1946 • पासपोर्ट अधिनियम, 1967	-	○ **विस्तार (2005):** सभी देशों के PIO, OCI बन सकते हैं। ○ PIO कार्ड + OCI = 9 जनवरी, 2015 ○ **अपवाद:** पाकिस्तान और बांग्लादेश

4) Citizenship for Foreigners

1) In the year 2000, a committee was formed under the chairmanship of Dr. L. M. Singhvi.

2) 9 January → **Pravasi Bharatiya Divas (2003)**

Category	Description
Non-Resident Indian (NRI)	*Those Indian citizens who live abroad. Staying abroad for 182 days or more on a visa.*
Person of Indian Origin (PIO)	*Those foreign citizens whose ancestors were Indian.*
Overseas Citizen of India (OCI)	*Those who have been granted special status by India.*

Description	**1. NRI (Non-Resident Indian)**	**2. PIO (Person of Indian Origin)**	**3. OCI (Overseas Citizenship of India)**
Citizenship / Definition	Fully an Indian citizen	Currently not an Indian citizen	This is not full citizenship, only a Status
Residence / Year of Issue	Staying abroad for 182 days or more on a visa	PIO Card mainly issued in 2002	**Started** : 2003 Committee: L. M. Singhvi **Committee** (Formed 2000 Report 2002)
Related Acts / Extension	• Passport (Entry into India) Act, 1920 • Foreigners Act, 1946 • Passport Act, 1967	—	○ Extension (2005) : PIOs of all countries can become OCI. ○ PIO Card + OCI = 9 January, 2015 ○ Exception : Pakistan

आधार	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)	जनगणना (Census)
कानूनी आधार	नागरिकता अधिनियम, 1955	जनगणना अधिनियम, 1948
उद्देश्य	व्यक्तियों की पहचान का डेटाबेस बनाना	देश की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और समाज का समग्र (Macro) आंकड़ा जुटाना
डेटा की गोपनीयता	व्यक्ति विशेष का डेटा (Identity) सरकारी उपयोग के लिए उपलब्ध होता है	जनगणना का डेटा पूरी तरह से गोपनीय होता है, इसे किसी व्यक्ति विशेष की पहचान के लिए इस्तेमाल नही कर सकते
लक्षित समूह	केवल 'सामान्य निवासियों' का विवरण	देश के सभी निवासियों का व्यापक विवरण

Basis	National Population Register (NPR)	Census
Legal Basis	Citizenship Act, 1955	Census Act, 1948
Purpose	To create a database of identification of individuals	To collect macro-level data on the country's population, economy, and society
Data Confidentiality	Data of specific individuals (Identity) is available for government use	Census data is completely confidential; it cannot be used to identify any specific individual
Target Group	Details of only 'usual residents'	Comprehensive details of all residents of the country